प्रेषक,

ई–मेल द्वारा

निदेशक/एस.एल.एन.ए.
नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश
8 वॉ तल, इन्दिरा भवन
लखनऊ।

सेवा में,

(1)समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।

पत्रांकः पी.एम.यू./1305/ 412/एस.बी.एम./2015 दिनांक 08 जनवरी, 2015

विषयः **''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम** के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में **शौचालयों** सम्बंधी **''कार्य योजना''** के सम्बंध में।

महोदय,

सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या क्यू–15014/2/2009–सी.पी.एच.ई.ई.ओ. दिनांक 7.11.2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समस्त नगरों में वित्त पोषण का स्वरूप तैयार किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशानिर्देश शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट www.moud.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त के अनुसार निम्नलिखित का प्रस्ताव हैः–

(1) प्रत्येक घरेलू शौचालय हेतु रू. 4000/–;
(2) सामुदायिक शौचालयों हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत वी.जी.एफ़. (Viability Gap Funding);
(3) सार्वजनिक शौचालयों हेतु 100 प्रतिशत निजी निवेश;
(4) सालिड वेस्ट मैनेजमेंट(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) हेतु अधिकतम 20 प्रतिशत वी.जी.एफ़.।

इनके अन्तर्गत परियोजनाओं का कियान्वयन राज्य सरकार की सहभागिता, निजी सेक्टर के निवेश, कारपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी फ़ण्ड, लाभार्थियों की सहभागिता तथा भारत सरकार के उपरिलिखित वित्तीय सहयोग से किया जायेगा। उपर्युक्त दिशानिर्देश के परिप्रेक्ष्य में 'स्वच्छ भारत मिशन' के लक्ष्य को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती **2 अक्टूबर, 2019** तक प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या 345जीआई/नौ–5–2014–411सा/14 दिनांक 1.1.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी नगरीय निकायों से अपेक्षा की गई है कि सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पी.पी.पी. (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर **कार्य योजना** तैयार करें एवं इस हेतु आवश्यक भूमि को चिन्हित करके कार्यवाही करें। घरों में शौचालय निर्माण आदि हेतु अनुदान/प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लिया जाना है।

कृपया उपरोक्तानुसार वांछित **कार्य योजना** शीर्ष प्राथमिकता पर इस निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

2– शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में एक **"कान्सेप्ट नोट"** 30 जनवरी, 2015 तक प्रेषित किया जाय। उपरोक्त नोट को तैयार किये जाने हेतु **संलग्न प्रारूप** पर शौचालयों के सम्बंध में सूचना अत्यन्त आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना इस निदेशालय को ई–मेल के पते diruplb2012@gmail.com पर दिनांक **19.1.2015** तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत।

भवदीय

(पी. के. सिंह)
निदेशक/एस.एल.एन.ए.

पृ. सं. एवं दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित –

1– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 1.1.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– निदेशक, सी. एण्ड डी. एस., उ. प्र. जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3– सहायक निदेशक(लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– टीम लीडर(पी.एम.यू.)/टीम लीडर(आर.पी.एम.सी.), नगरीय निकाय निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– श्री अमरेश सिंह चौहान, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को वांछित सूचनाएं संलग्न प्रारूप पर संकलित कर टीम लीडर(पी.एम.यू.) को उपलब्ध कराने हेतु।

6– जूनियर प्रोग्रामर, निदेशालय को इस पत्र को संलग्नक सहित निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(पी. के. सिंह)
निदेशक/एस.एल.एन.ए.

"स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के **शहरी क्षेत्रों** में नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा "**कान्सेप्ट नोट**" तैयार किये जाने हेतु समस्त नागर निकायों से **शौचालय** से सम्बंधित **वांछित सूचना** का **प्रारूप**

नागर निकाय का नाम	जनपद का नाम	नागर निकाय में कुल आवासीय परिसरों (हाउस होलड्स) की संख्या	आवासीय परिसरों की संख्या जिनमें शौचालय उपलब्ध नहीं है	आवासीय परिसरों की संख्या जिनमें शौचालय, जो सीवर प्रणाली/ सेप्टिक टैंक से जुड़े हों, उपलब्ध है	आवासीय परिसरों की संख्या जिनमें पिट (गड्ढा युक्त) शौचालय उपलब्ध है	आवासीय परिसरों की संख्या जिनमें बहाव प्रकार आदि प्रकार के शौचालय उपलब्ध है	सामुदायिक शौचालयों (कमयुनिटि टायलेट) की आवश्यकता (संख्या)	सार्वजनिक शौचालयों (पब्लिक टायलेट) की आवश्यकता (संख्या)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अधिकृत प्राधिकारी /अधिशासी अधिकारी
का नाम व हस्ताक्षर, दिनांक सहित

प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या- 345जीआई/नौ-5-2014-411सा/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
त्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 01 जनवरी, 2015 ~~दिसम्बर, 2014~~

विषयः **'स्वच्छ भारत मिशन'** के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-क्यू-15014/2/2009-सीपीएचईईओ, दिनांक 07.11.2014 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश के सभी 4041 नगरों में वित्त पोषण का स्वरूप तैयार किया गया है, जिसके अनुसार (1) प्रत्येक घरेलू शौचालय हेतु रू0 4000/- (2) सामुदायिक शौचालयों हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत वीजीएफ- Viability Gap Funding (3) सार्वजनिक शौचालयों हेतु 100 प्रतिशत निजी निवेश (4) सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु अधिकतम 20 प्रतिशत वीजीएफ (Viability Gap Funding) का प्रस्ताव है। इनके अन्तर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार की सहभागिता, निजी सेक्टर के निवेश, कारपोरेट सोशल रेस्पांबिलिटी फण्ड, लाभार्थियों की सहभागिता तथा भारत सरकार के वीजीएफ के लिये प्रोत्साहन/सहयोग से किया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को 05 वर्ष में प्राप्त करने हेतु एक **कार्य योजना** तैयार कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में सभी नगरीय निकायों से अपेक्षा की गयी है कि सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पीपीपी आधार पर कार्य योजना तैयार करें एवं इस हेतु आवश्यक भूमि को चिन्हित करके उसको अधिग्रहित करें। घरों में शौचालय निर्माण आदि हेतु अनुदान/प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लिया जा सकता है।

अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर कराने तथा तद्नुसार प्रदेश की नगरीय निकायों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। इसकी प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

31/12/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 345जीआई(1)/नौ-5-2014-411सा/14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 07.11.2014 के क्रम में।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल/सूडा।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

IS/GI/2014

शंकर अग्रवाल, आई.ए.एस.
SHANKAR AGGARWAL, IAS

सत्यमेव जयते

सचिव भारत सरकार
Secretary to the Government of India

शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110011
Tel.: 23062377, Fax : 23061459
E-mail : secyurban@nic.in
URL : http://moud.gov.in

D.O. No.Q-15014/2/2009-CPHEEO

Dated 7th November, 2014

सं० 20990/स०न०वि०/2014

Dear

You are aware that the Government of India has launched "Swachh Bharat Mission" (SBM) on 2nd October, 2014 with a target to make the country clean by 2nd October, 2019. The Mission covers all 4041 statutory cities and towns as per census 2011 and the components eligible under SBM with broad funding pattern are (i) Household Toilet - Rs.4000 per toilet as an incentive; (ii) Community Toilet – max. 40% VGF; (iii) Public toilets - 100% private investment; and (iv) Solid Waste Management Project – max. 20% VGF. The projects will be implemented involving substantial private sector investment, contribution from beneficiaries and Government incentive/support for viability gap funding (VGF).

(श्री प्रकाश सिंह)
नगर विकास, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
उ० प्र० शासन

2 The scheme guidelines are presently under finalisation and would be communicated shortly. Draft guidelines are available on Ministry's website www.moud.gov.in and may be referred to for comments/preparation of implementation plan. In the meantime, you are requested to prepare an action plan for achieving the target of "Swachh Bharat Mission" (SBM) within five years period (with year wise breakup) in respect of soft and physical components of the Mission. Also, all ULBs may be directed to prepare Plan for construction of public toilets/community toilets as well as solid waste management, on PPP basis and requisite land may be identified and possession taken at earliest possible. Further, to ensure that the programme is smoothly implemented, State Government may like to use a website/IT platform where all beneficiaries can send the request online seeking Government grant/incentive for the construction of household toilets in the indicative **Format I** enclosed.

With Best Regards

Yours Sincerely,

(Shankar Aggarwal)

Shri Alok Ranjan, IAS
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Secretariat, Lucknow-226001
Tel: 0522-2221599, 0522-2238212, 0522-2238212
Fax: 0522-2239283
Email: csup@nic.in

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव
उ० प्र० शासन

नगर विकास विभाग

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Swachh Bharat Mission

Format I: For data on Toilet

[This form to be downloaded/printed and duly filled in and signed copy to be scanned and submitted on the website]

	(A) Geographical Particulars
1.	State: ⇦ *In Drop Down List Format*
2.	Distt.: ⇦ *In Drop Down List Format*
3.	Block: ⇦ *In Drop Down List Format*
4.	Tehsil: ⇦ *In Drop Down List Format*
5.	Town/City: ⇦ *In Drop Down List Format*
6.	Ward: ⇦ *In Drop Down List Format*
	(B) Toilet Owner's Particulars
1.	Name of the Applicant:
2.	Profession:
3.	Father's Name:
4.	Mother's Name:
5.	Address:
6.	Contact No.: Landline Mobile
7.	Aadhar Card No.:
8.	Bank A/c details: A/c No Name of Bank: ⇦ *In Drop Down List Format* Bank Branch: ⇦ *In Drop Down List Format* *Note: The funds will be transferred through Electronic Transfer*
9.	Status of the Existing Toilet: i) Not Existing ☐ ii) Dry Latrine ☐ iii) Bahao type Latrine ☐ iv) Unsanitary latrine based on single pit latrine ☐
	(C) Undertaking
	I undertake that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief and in case of any information is found to be false/ suppressed, State Government/ Government of India will initiate suitable action against me. Signature of Applicant
	(D) Reference of Two Persons vouching for the Toilet Owner

(I)	(II)
Name: Father's Name: Contact Address: City: ⇦ *In Drop Down List Format* State: ⇦ *In Drop Down List Format* Contact No.: Landline: Mobile: Date: Signature	Name: Father's Name: Contact Address: City: ⇦ *In Drop Down List Format* State: ⇦ *In Drop Down List Format* Contact No.: Landline: Mobile: Date: Signature

Open Defication is the Shame on the Nation